रजिस्टर्ड नं० सी०/एस० एच० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला सोमवार, 21 मार्च, 1988/1 चैत्र, 1910

हिमाचल प्रदेश सरकार
VIDHAN SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

Shimla, 4, the 16th March, 1988

No 1-14/880 VS.—In pursuance to rule 135 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Himachal Pradesh Legislative Assembly, 1973. The Himachal Pradesh.

Approppriation Bill, 1988 (Bill No. 1 of 1988)" having been introduced on the 16th March, 1988, in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha, is hereby published in the Gazette.

LAXMAN SINGH
Secretary.

1988 का विधेयक संख्यांक 1.

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 1988

(विधान सभा में यथा पुरःस्थापित)

31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय अतिरिक्त धन-राशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के उनतालिसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1988 है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1987-88 के लिए 91,35,03,057 रुपये की और राशि जारी करना ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक अतिरिक्त धन-राशियां, जिनका योग 91,35,03,057 रुपये (इकानवें करोड़, पैंतीस लाख, तीन हजार, सतावन रुपये) है, संदत्त और उपयोजित की जाएं जिनका वित्तीय वर्ष 1987-88 की अवधि में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा ।

विनियोग ।

3. इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत धन-राशियों का इस अधिनियम की धारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजन किया जाएगा ।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

1	2		3		
मांग संख्या	सेवाएं एवं प्रयोजन		निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
			विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	जोड़
			रुपए	रुपए	रुपए
1.	विधान सभा और निर्वाचन	(राजस्व)	4,60,000	25,100	4,85,100
2.	राज्यपाल और मन्त्रि परिषद	(राजस्व)	7,77,000	—	7,77,000
3.	न्याय प्रशासन	(राजस्व)	35,63,000	12,74,000	48,37,000
4.	सामान्य प्रशासन	(राजस्व)	1,68,99,449	3,67,000	1,72,66,449
		(पूंजी)	7,27,000	—	7,27,000
5.	भू-राजस्व	(राजस्व)	4,95,44,000	—	4,95,44,000
6.	आबकारी और कराधान	(राजस्व)	25,29,000	—	25,29,000
7.	पुलिस और सम्बद्ध संगठन	(राजस्व)	2,33,43,700	1,49,635	2,34,93,335
8.	शिक्षा, खेलें, तथा कला और संस्कृति	(राजस्व)	14,25,11,000	—	14,25,11,000
		(पूंजी)	—	6,80,100	6,80,100
9.	चिकित्सा और परिवार कल्याण	(राजस्व)	3,08,19,000	38,700	3,08,57,700
		(पूंजी	13,34,000	—	13,34,000
10.	लोक निर्माण	(राजस्व)	3,72,78,000	—	3,72,78,000
		(पूंजी)	12,00,000	—	12,00,000
11.	कृषि	(राजस्व)	1,76,41,600	11,650	1,76,53,250
		(पूंजी)	2,45,73,000	—	2,45,73,000
12.	सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण	(राजस्व)	46,00,000	—	46,00,000
		(पूंजी)	55,01,000	—	55,01,000
13.	भूमि और जल संरक्षण	(राजस्व)	100	75,300	75,400
		(पूंजी)	1,00,000	—	1,00,000
14.	पशुपालन और दुग्ध विकास	(राजस्व)	1,36,41,000	1,42,400	1,37,83,400
		(पूंजी)	21,00,000	—	21,00,000
15.	मत्स्य	(राजस्व)	12,04,000	—	12,04,000
16.	वन और वन्य जीवन	(राजस्व)	1,83,53,100	2,90,958	1,86,44,058
		(पूंजी)	19,84,900	—	19,84,900

1	2		3		
			रुपये	रुपये	रुपये
17.	सड़कें और पुल	(राजस्व)	1,18,07,000	—	1,18,07,000
		(पूंजी)	8,95,03,000	2,12,223	8,97,15,223
18.	पूर्ति, उद्योग और खनिज	(राजस्व)	2,95,42,809	9,946	2,95,52,755
		(पूंजी)	1,03,75,000	—	1,03,75,000
19.	सामाजिक सुरक्षा कल्याण (पोषाहार सहित)	(राजस्व)	57,60,000	2,41,650	60,01,650
		(पूंजी)	3,00,000	—	3,00,000
20.	ग्रामीण विकास	(राजस्व)	2,22,86,000	1,500	2,22,87,500
21.	सहकारिता	(राजस्व)	77,51,000	—	77,51,000
22.	खाद्य एवं भण्डारण	(राजस्व)	18,57,000	—	18,57,000
		(पूंजी)	5,40,35,100	—	5,40,35,100
23.	जल और विद्युत विकास	(पूंजी)	17,00,000	—	17,00,000
24.	लेखन सामग्री और मुद्रण	(राजस्व)	28,00,000	—	28,00,000
25.	सड़क, जल परिवहन और नगर विमानन	(राजस्व)	1,02,19,000	—	1,02,19,000
		(पूंजी)	2,68,51,000	37,912	2,68,88,912
27.	श्रम और रोजगार	(राजस्व)	40,72,000	—	40,72,000
		(पूंजी)	5,20,000	—	5,20,000
28.	जलापूर्ति, सफाई, आवास और नगर विकास	(राजस्व)	95,52,000	71,535	96,23,535
		(पूंजी)	7,12,56,000	1,62,995	7,14,18,995
29.	वित्त	(राजस्व)	9,55,51,000	1,84,55,000	11,40,06,000
30.	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	(राजस्व)	1,85,695	—	1,85,695
		(पूंजी)	1,000	—	1,000
31.	जन-जातीय विकास	(राजस्व)	2,25,71,000	—	2,25,71,000
		(पूंजी)	1,20,76,000	—	1,20,76,000
	कुल जोड़		89,12,55,453	2,22,47,604	91,35,03,057
		(राजस्व)	58,71,18,453	2,11,54,374	60,82,72,827
		(पूंजी)	30,41,37,000	10,93,230	30,52,30,230

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के साथ पठित अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1987-88 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमानित व्ययों के सम्बन्ध में संचित निधि पर प्रभारित व्ययों और विधान सभा द्वारा यथा दसमत अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अपेक्षित अतिरिक्त धन के विनियोजन का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है ।

वीरभद्र सिंह
मुख्य मन्त्री ।

शिमला :
16 मार्च, 1988.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[वित्त विभाग फाइल सं0 फिन-ए-सी-(2) 20/87-III]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 1988 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते है।

Authoritative English text of Himachal Pradesh Viniyog Vidheyak, 1988 (1988 *Ka Vidheyak Sankhyank* 1) *as required under Clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

Bill No. 1 of 1988.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION BILL, 1988

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year ending on the 31st day of March, 1988.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Thirty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation Act, 1988.

Issue of a further sum of Rs. 91,35,03,057 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 1987-88.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 91,35,03,057 (Ninety-one crores, thirty-five lakhs, three thousand and fifty seven rupees) towards defraying the charges which will come in course of payment during the financial year 1987-88 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be further appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the period specified under section 2 of this Act.

THE SCHEDULE

(*See* Sections 2 and 3)

1	2		3		
			Sums not exceeding		
De-mand No.	Services and purposes		Voted by the Legis-lative Ass-embly	*Charged* on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
1.	Vidhan Sabha and Election	(Revenue)	4,60,000	25,100	4,85,100
2.	Governor and Council of Ministers	(Revenue)	7,77,000	—	7,77,000
3.	Administration of Justi e	(Revenue)	35,63,000	12,74,000	48,37,000
4.	General Administration	(Revenue)	1,68,99,449	3,67,000	1,72,66,449
		(Capital)	7,27,000	—	7,27,000
5.	Land Revenue	(Revenue)	4,95,44,000	—	4,95,44,000
6.	Excise and Taxation	(Revenue)	25,29,000	—	25,29,000
7.	Police and Allied Organisations	(Revenue)	2,33,43,700	1,49,635	2,34,93,335
8.	Education, Sports and Arts and Culture	(Revenue)	14,25,11,000	—	14,25,11,000
		(Capital)	—	6,80,100	6,80,100
9.	Health and Family Welfare	(Revenue)	3,08,19,000	38,700	3,08,57,700
		(Capital)	13,34,000	—	13,34,000
10.	Public Works	(Revenue)	3,72,78,000	—	3,72,78,000
		(Capital)	12,00,000	—	12,00,000
11.	Agriculture	(Revenue)	1,76,41,600	11,650	1,76,53,250
		(Capital)	2,45,73,000	—	2,45,73,000
12.	Irrigation and Flood Control	(Revenue)	46 00.000	—	46,00,000
		(Capital)	55,01,000	—	55,01,000
13.	Soil and Water Conservation	(Revenue)	100	75,300	75,400
		(Capital)	1,00,000	—	1,00,000
14.	Animal Husbandry and Dairy Development	(Revenue)	1,36,41,000	1,42,400	1,37,83,400
		(Capital)	21,00,000	—	21,00,000
15.	Fisheries	(Revenue)	12,04,000	—	12,04,000
16.	Forest and Wild Life	(Revenue)	1,83,53,100	2,90,958	1,86,44,058
		(Capital)	19,84,900	—	19,84,900
17.	Roads and Bridges	(Revenue)	1,18,07,000	—	1,18,07,000
		(Capital)	8,95,03,000	2,12,223	8,97,15,223
18.	Supplies, Industries and Minerals	(Revenue)	2,95,42,809	9,946	2,95,52,755
		(Capital)	1,03,75,000	—	1,03,75,000
19.	Social Security, Welfare (including nutrition)	(Revenue)	57,60.000	2,41,650	60,01,650
		(Capital)	3,00,000	—	3,00,000
20	Rural Development	(Revenue)	2,22,86,000	1,500	2,22,87,500
21.	Co-operation	(Revenue)	77,51,000	—	77,51,000
22.	Food and Warehousing	(Revenue)	18,57,000	—	18,57,000
		(Capital)	5,40,35,100	—	5,40,35,100
23.	Water and Power Development	(Capital)	17,00,000	—	17,00,000
24.	Stationery and Printing	(Revenue)	28,00,000	—	28,00,000

1	2		3		
			Rs.	Rs.	Rs.
25.	Road/Water Transport and Civil Aviation.	(Revenue)	1,02,19,000	—	1,02,19,000
		(Capital)	2,68,51,000	37,912	2,68,88,912
27.	Labour and Emlpoyment	(Revenue)	40,72,000	—	40,72,000
		(Capital)	5,20,000	—	5,20,000
28.	Water Supply, Sanitation, Housing and Urban Development.	(Revenue)	95,52,000	71,535	96,23,535
		(Capital)	7,12,56,000	1,62,995	7,14,18,995
29.	Finance	(Revenue)	9,55,51,000	1,84,55,000	11,40,06,000
30.	Loans to Government servants	(Revenue)	1,85,695	—	1,85,695
		(Capital)	1,000	—	1,000
31.	Tribal Development	(Revenue)	2,25,71,000	—	2,25,71,000
		(Capital)	1,20,76,000	—	1,20,76,000
	Grand Total	..	89,12,55,453	2,22,47,604	91,35,03,057
	Revenue	..	58,71,18,453	2,11,54,374	60,82,72,827
	Capital	..	30,41,37,000	10,93,230	30,52,30,230

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of Clause (1) of Article 204 read with Article 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys further required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly in respect of the estimated expenditure of the Government of Himachal Pradesh for the financial year 1987-88.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA :
The 16th March, 1988.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[*Finance Department File No. Fin. A-C*(2) 20/87-*III*]

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Appropriation Bill, 1988, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the said Bill in the Legislative Assembly.